

दि कार्मिक पोर्ट

वर्ष : 6, अंक : 30

(प्रति बुधवार), इन्डौर, 17 मार्च से 23 मार्च 2021

पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल

देश में वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर तक पहुंच चुका है। इस बात का अंदाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 अकेले भारत के हैं। दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर होने के साथ-साथ टॉप 10 में भी शुमार रही। हालांकि, वर्ष 2020 में पिछले

साल के मुकाबले दिल्ली की वायु गुणवत्ता 15 फीसद सुधरी है। वायु गुणवत्ता का आंकलन करने वाले स्वीस समूह आइक्यूएयर की तरफ से मंगलवार को जारी बल्ट एयर क्लालिटी रिपोर्ट-2020 में यह खुलासा हुआ है। देश की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। सूची में शामिल दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारत के हैं। शिनजियांग सर्वाधिक प्रदूषित शहर, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया है। हालांकि, इसके बाद के नौ सर्वाधिक प्रदूषित शहर भारत के हैं। गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवाड़ी व दिल्ली का नंबर आता है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर



नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा व मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), भिवाड़ी (राजस्थान), फरीदाबाद, जीद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक को अलग शहर बताया गया हो, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। 106 देश रैंकिंग में शामिल दुनिया के विभिन्न शहरों की रैंकिंग हवा में पीएम 2.5 की मौजूदगी के आधार पर की गई है। 106 देशों के विभिन्न शहरों की हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मीटर (पीएम) 2.5 के आंकड़े बहां स्थित निगरानी केंद्रों से लिए गए। अधिकांश निगरानी केंद्रों का संचालन सरकारे करती हैं। पीएम 2.5 ऐसा प्रदूषक तत्व है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। पीएम 2.5 उस प्रदूषक तत्व को कहा जाता है, जिसका व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है। बाहनों से सबसे ज्यादा पीएम 2.5 उत्सर्जन देश में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में परिवहन, जैविक ईंधन, हालांकि, सबसे ज्यादा पीएम 2.5 का उत्सर्जन बाहनों के जरिये होता है।



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

नारी है जग की नाड़ी, सांसे हैं जग की इससे जुड़ी, ये ना हो तो कैसे करूं कल्पना सुंदर जीवन की

भीयापुरा। महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं को उनके अधिकार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध व समर्पित SENSED सोसाइटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर SENSED सोसायटी द्वारा औबेदुल्लागंज क्षेत्र के पिछड़े गांव भीयापुर में महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म विषय पर गांव की महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया द्वारा महिलाओं जानी मानी अंतरराष्ट्रीय योग गुरु श्रीमती हितांशी जैन का ऑनलाइन मासिक धर्म पर चर्चा का आयोजन किया गया ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शिक्षिकाओं ने नाट्य मंचन द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया SENSED सोसाइटी की सेक्रेटरी डॉ. सोनल मेहता ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई और सोसाइटी द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों और उद्देश्य को समझाया। इस समारोह में उपस्थित सभी महिलाओं को सोसायटी द्वारा सेनेटरी पैड भी दिए गए ज्ञात हो की सोसाइटी द्वारा इस गांव में महिलाओं के लिये मिलाई प्रशिक्षण का कार्य संकाया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।

समुद्र के जल स्तर ने वृद्धि होने से भूजल और पानी के स्रोतों ने मिल रहा है वेस्ट वाटर

मुंबई। एक वैश्विक अनुमान के अनुसार समुद्र का जल स्तर 2100 तक 0.3-1 मीटर तक बढ़ने के आसार हैं, एक अन्य अनुमान में इसके 2 मीटर या उससे अधिक बढ़ने की आशंका जताई गई है। परिगणित स्प्रिंग ज्वार के समुद्र पर खतरनाक असर पड़ने के आसार हैं, जिसमें समुद्र स्तर वृद्धि (एमएलआर) प्रभाव, जैसे बाढ़, समुद्र तट का कटाव और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आदि है। हालांकि समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रभावों का पता लगाने वाले अधिकांश अध्ययनों में सतही बाढ़ और समुद्री जल के घुसपैठ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, हाल के कुछ अध्ययनों में सतही बाढ़ के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

जब हम लोग समुद्र के स्तर में वृद्धि के बारे में चाहते हैं, तो हम आमतौर पर तटीय कटाव के बारे में सोचते हैं। हालांकि, हाल के कंप्यूटर मॉडलिंग अध्ययनों से पता चला है कि तटीय अपशिष्ट जल संरचना, जिसमें सीधर लाइनें और तरल कचरा शामिल हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि होने की वजह से बाढ़ आती है और प्रदूषित जल, भू-जल और अन्य स्रोतों में मिल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई (यूएच) में माओना के पृथ्वी वैज्ञानिकों ने एक नया अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चलता है कि महासागर के उच्च जल स्तर के कारण अपशिष्ट जल बरसाती नालों और समुद्र के किनारों पर मिलता है। जिसके कारण समुद्र के किनारे के पानी की गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर चुरा प्रभाव पड़ रहा है।

इस अध्ययन की अगुवाई पोस्टबैंकटरल शोधकर्ता द्रिस्टा मैकेंजी ने किया है और इसमें यूएच सी ग्रांट तटीय भूविज्ञानी शेल्फी हैबेल और यूएच सागर ग्रोसन ओशन एंड अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसओईएसटी) के सलाहकार और एसोसिएट प्रोफेसर हेनरिकेटा दुलाई ने सहयोग दिया है। टीम ने वसंत में आने वाले ज्वार के दौरान निचले इलाकों में तटीय महासागर के पानी और बरसाती नालों के पानी (स्ट्रोम ड्रेन वाटर) का आकलन किया, जिससे भविष्य के समुद्र स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। अपशिष्ट जल अवसंरचना (वेस्टवाटर इंफ्रास्ट्रक्चर), भूजल और तटीय महासागर के बीच संबंध को समझने के लिए, शोधकर्ताओं ने प्रत्येक स्थान पर मौजूद भूजल निकलने की जगह और अपशिष्ट जल का पता लगाने के लिए एक विशेष केमिकल का उपयोग किया। रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है जो भूजल की उपस्थिति के बारे में जानकारी देती है, जबकि अपशिष्ट जल का पता मानव स्रोतों से विशिष्ट कार्बनिक प्रदूषक जैसे कैफीन और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं को मापने से लगाया जा सकता है। मैकेंजी ने कहा हमारे नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में, समुद्र तट में मिलने वाले पानी की बरसाती नालियां (स्टॉर्म ड्रेन) भू-जल को आज अपशिष्ट जल प्रदूषित कर रहा है। निचले इलाकों के आंतरिक क्षेत्रों में, पानी की बरसाती नालियां (स्टॉर्म ड्रेन) वसंत में आने वाले ज्वार को सैलाब में बदल सकती हैं। इस अध्ययन ने दिखाया कि एक ही समय में अपशिष्ट जल के निपटारे के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे के अलावा बरसाती नालियां (स्टॉर्म ड्रेन) से भी बहने लगता है। उच्च ज्वार के दौरान, सड़कों और फुटपाथों पर बहने वाला गंदा, अनुपचारित बरसाती नालों से बहकर समुद्र तक पहुंच जाता है। यह दूषित बाढ़ का पानी आपातकालीन बाहनों की



आवाजाही सहित यातायात को बाधित करता है, साथ ही इस पानी से मानव स्वास्थ्य को भी खतरा होता है। टीम ने सड़कों और फुटपाथों पर बहने वाले पाने में कई तरह के मानव निर्मित दूषित पदार्थ पाए जो जलीय जीवों के लिए खतरनाक हैं। यह समुद्र के तटीय जीवों के लिए जोखिम भरा है जहां पर भूजल और बरसाती नालियां बह रही हो। यह अध्ययन लिमोलॉजी और ओशनोग्राफी लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। मैकेंजी ने कहा कई लोग समुद्र के स्तर में वृद्धि को भविष्य की समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में, हम पहले से ही इन प्रभावों को देख रहे हैं। इसके अलावा, मानव स्वास्थ्य, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र और अपशिष्ट जल अवसंरचना के लिए इन खतरों का भविष्य में और भी अधिक भयंकर होने की आशंका है। यह अध्ययन बताता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तटीय अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस अध्ययन का उद्देश्य है। मैकेंजी ने कहा समुद्र के तटीय इलाके की नगर पालिकाओं को इससे निपटने की रणनीतियां बनानी चाहिए तथा उन्हें लागू किया जाना चाहिए। उन्हें अपशिष्ट जल अवसंरचना, पीने के पानी के संसाधनों के बीच बढ़ती नजदीकी में भी सुधार करना होगा। हमें बुनियादी ढांचे पर विचार करने की आवश्यकता है, जिससे बाढ़ कम से कम आए और दूषित पानी के संपर्क से भी बचा जा सके। इससे प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की संख्या कम हो जाती है, जैसे कि बरसाती नालों के लिए एक तरफा बाल्व लगाना, ताकि उनमें अनुपचारित या प्रदूषित पानी प्रवेश ने कर पाए। खराब सीधर लाइनों में सुधार करना और ऊचे पैदल चलने वाले ग्रस्तों और सड़कों का निर्माण करना आदि। (साभार)

फेस मास्क बन रहे हैं दूसरी बड़ी प्लास्टिक समस्या

फेस मास्क कोरोनावायरस और अन्य बीमारियों के फैलने से रोकने में मदद करते हैं, कोविड-19 महामारी को नियन्त्रित करने के लिए लगभग सभी स्वास्थ्य समूहों और देशों द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को मास्क का उपयोग करने को कहा गया। प्लास्टिक उत्पादों की तरह - फैक्ने वाली जीवन शैली - के तहत, डिस्पोजेबल मास्क 2003 के सार्व से कोविड-19 तक महामारी का प्रतीक रहा है। हालांकि इस बात की कोई अधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि कितने मास्कों का निपटान किया जाता है। हाल के अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में हम हर महीने 129 अरब फेस मास्कों का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर मिनट 30 लाख मास्कों का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक माइक्रोफाइबर से बने डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं। शोध में चेतावनी दी गई है कि मास्कों के अनुचित तरीके से निपटान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से पर्यावरणीय खतरे बढ़ सकते हैं, इन खतरों की पहचान कर इसे अगली प्लास्टिक की समस्या बनने से रोकना आवश्यक है। इस शोध की अगुवाई दक्षिण डेनमार्क विश्वविद्यालय के पर्यावरण विषयविज्ञानी एल्विस जेन्सो जू और प्रिंस्टन विश्वविद्यालय से मिक्रिल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जियाओंग जेसन रेन ने की है। डिस्पोजेबल मास्क प्लास्टिक से बने उत्पाद हैं, जिनका आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक रूप से फैलने वाले सूक्ष्म प्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक जैसे छोटे प्लास्टिक कणों में टूट सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क का विशाल उत्पादन प्लास्टिक की बोतलों की तर्ज पर हो रहा है, जिनका

प्रति माह उत्पादन 4300 करोड़ होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने कहा हालांकि, प्लास्टिक की बोतलों को जिनमें से ऐप. 25 पीसीटी. रीसायकल किया जाता है, लेकिन मास्क रीसायकल पर कोई अधिकारिक मार्गदर्शन नहीं है, जिससे इसे ठोस कचरे के रूप में निपटाए जाने के अधिक आसार हैं। यदि रीसायकिलंग करके निपटाया नहीं जाता है, तो अन्य प्लास्टिक कचरे की तरह, डिस्पोजेबल कहे जाने वाले मास्क पर्यावरण, ताजे पानी के स्रोतों और महासागरों में समासकता है, जहां ये कम समय में बड़ी संख्या में सूक्ष्म आकार के कणों में टूटकर (5 मिमी से छोटे) कण उत्पन्न कर सकता है। एक सासाह के अंदर ये कण अति सूक्ष्म 1 माइक्रोमीटर से छोटे कणों में टूट जाता है जिसे नैनोप्लास्टिक कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि एक नई और बड़ी चिंता यह है कि मास्क सीधे अति सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक फाइबर (9 टिल्ड) 1 से 10 माइक्रोमीटर की मोटाई) से बनाए जाते हैं। जब यह वातावरण में टूटता है, तो मास्क प्लास्टिक बैग की तुलना में अधिक सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक कणों को आसानी और तेजी से फेला सकता है।



Vishnu Prasad/ANI

मेघालय में अवैध खनन रोकने के लिए एनजीटी ने बनाई समिति

नई दिल्ली। मेघालय में अवैध और गैर वैज्ञानिक तरीके से हो रहे खनन को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक 12 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति को मेघालय में गैर वैज्ञानिक और अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित किया गया है। साथ ही, इसका उद्देश्य पर्यावरण को फिर से बहाल करना, पीड़ितों का पुनर्वास करना और अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का प्रबंधन करना है। पर्यावरण मंत्रालय के अपर सचिव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

पूरा मामला मेघालय में कोयला खनन से जुड़ा है। जिसके चलते उन खानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ गया था, साथ ही इसके कारण पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। एनजीटी में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीट ने इस मामले पर 01 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया है। जिसमें अवैध खनन को देखते हुए एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 15 मार्च 2021 को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया

गया है। अपने आदेश में पीट ने कहा है कि चूंकि कोर्ट और उसके द्वारा बनाई समितियां इसकी निगरानी हमेशा नहीं कर सकते ऐसे में इसकी निगरानी 12 सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी। यह समिति महीने में एक बार बैठक करेगी और स्थिति का जायजा लेगी। साथ ही इस मामले में भावी कार्ययोजनाएं बनाएगी। साथ ही समिति पर गैर वैज्ञानिक और अवैध खनन को रोकने और पहले से ही खनन किए गए कोयले और अन्य सामग्री के निपटान की जिम्मेवारी होगी। साथ ही इस समिति पर इस मामले में उच्चतम न्यायालय एवं प्राधिकरण द्वारा दिए पिछले आदेशों के क्रियान्वयन का भी जिम्मा होगा। गौरतलब है कि पाबन्दी के बाबजूद मेघालय में अभी भी अवैध खनन रैट होल माइनिंग जारी है। अपने आदेश में एनजीटी ने साफ कर दिया कि जन विधास सिद्धांत के तहत राय सरकार दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा के काम करने के लिए बाध्य है। यह मामला 06 जुलाई 2012 को उस समय सामने आया था जब एक समाचार में 30 कोयला मजदूरों के खदान में फँसे होने की खबर सामने आई थी जिनमें से 15 की मौत

हो गई थी। 17 अप्रैल 2014 को इस मामले पर विचार करने के बाद एनजीटी ने मेघालय में रैट होल माइनिंग पर रोक लगा दी थी साथ ही राय सरकार को निर्देश दिया था कि वो सुनिश्चित करे कि

अगले आदेश तक राय में किसी भी तरह से कोयले का अवैध परिवहन नहीं होगा। इस आदेश के आधार पर राय में अवैध खनन को जांचने के लिए 09 जून 2014 को एक समिति गठित की गई थी। जिसके द्वारा 07 अक्टूबर 2017 को जारी रिपोर्ट से पता चला था कि राय में अवैध खनन के जरिए राय में करीब 63 लाख टन कोयला इकट्ठा है, जिसकी कीमत करीब 307 करोड़ रुपए है। इस मामले पर 31 जुलाई 2015 को भी एक आदेश ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद पिछली कार्यवाहियों के आधार पर 31 अगस्त 2018 को राय



में रैट होल माइनिंग और कोयले के परिवहन को अवैध घोषित कर दिया गया था। साथ ही इसके नियंत्रण की जिम्मेवारी राय सरकार को सौंप दी गई थी। इसके बाद 13 दिसंबर 2018 को एक बार फिर 15 खनिकों के खदान में फँसे होने की खबर सामने आई थी। जिस पर ट्रिब्यूनल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि राय में अभी भी अवैध खनन बदस्तूर जारी है। उस समय कोयले को 23,25,663.54 मीट्रिक टन मापा गया था। साथ ही कोर्ट ने इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को मापने के लिए अलग से अध्ययन करने की सिफारिश की गई थी। कोर्ट

ने पर्यावरण की बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही थी। वहीं राय सरकार द्वारा अपना काम ठीक से न करने के लिए जुर्माने के तौर पर 100 करोड़ रुपए सीपीसीबी के पास जमा कराने की बात कही थी। जिससे पर्यावरण की बहाली की जा सके। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2019 और 02 अगस्त 2019 को समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर 22 अगस्त 2019 को सुनवाई की गई थी। इस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 03 जुलाई 2019 को आदेश जारी किया था। 26 नवंबर 2019 को सीपीसीबी ने

भी इस मामले पर एक रिपोर्ट समिट की थी। जिसमें पर्यावरण की बहाली की बात की गई थी। साथ ही इस बीच इस मामले पर कई बार सुनवाई हुई है और समिति ने अपनी कई रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की है। 17 जनवरी 2020 को भी इस मामले पर एनजीटी ने आदेश जारी किया था। 27 जुलाई 2020 को भी इस मामले पर एक आदेश जारी किया गया था। इस मामले में 14 जनवरी 2021 को कोर्ट के सामने समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसके आधार पर एनजीटी ने अपना यह आदेश जारी किया है।

(साभार)

सहारा रेगिस्तान में मिला धरती से भी पुराना उल्कापिंड, जानें वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

अफ़्रीका के सहारा रेगिस्तान में शोधकर्ताओं ने एक उल्कापिंड का टुकड़ा खोजा है। जो धरती से भी पुराना है। विज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर ऐसे ग्रह का है, जिसका निर्माण तब शुरू हुआ जब पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं था। इस उल्कापिंड को Erg Chech 002 (EC 002) नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह 4.54 बिलियन साल पुराना है। इसका निर्माण एक प्रोटोप्लैनेट की पर्फीटी के अंदर हुआ है। दरअसल यह पत्थर अफ़्रीका के अलजीरिया के अंग चेच इयून सागर में मिला है। इसका वजह करीब 32 किलो है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्फीटी का टुकड़ा लाला की तरह पिछला हुआ होगा। इसके बजह करीब 63 किलो है। इसकी कीमत करीब 307 करोड़ रुपए है। इस मामले पर 31 जुलाई 2015 को भी एक आदेश ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद पिछली कार्यवाहियों के आधार पर 31 अगस्त 2018 को राय



2030 तक अपने 10 फीसदी एसडीजी लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर पाएंगे एरियाई देश-संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली। यदि मौजूदा रफतार से चलता रहा तो एशिया-पैसिफिक क्षेत्र 2030 तक अपने 10 फीसदी एसडीजी लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर पाएंगा। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2021 में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनएस?केप) के तहत 2030 तक सतत विकास से जुड़े 17 लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था।

जिसमें गरीबी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य, सब के लिए भोजन, बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर काम और आर्थिक विकास, जैवविवरधता, इनोवेशन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और असमानताओं को कम करना जैसे मुद्दे शामिल थे। यदि इन लक्ष्यों को हासिल करने के सकारात्मक कृदमों की ओर देखें तो इस क्षेत्र में सबसे यादा प्रगति लक्ष्य 3 जोकि स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की बात करता है, उसमें हुई है। इसके बाद इनोवेशन और बुनियादी ढांचे (लक्ष्य 9) में भी प्रगति देखने को मिली है। साथ ही, गरीबी उन्मूलन (लक्ष्य 1), जीरो हांगर (लक्ष्य 2) और बेहतर शिक्षा (लक्ष्य 4), असमानता (लक्ष्य 10) और आपसी साझेदारी (लक्ष्य 17) में भी कुछ प्रगति हुई है, हालांकि इसके बावजूद वो इतनी नहीं है जिसे कहा जा सके कि वो 2030 के लक्ष्यों को हासिल कर लेगी। इसके अलावा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन (लक्ष्य 13) और जलीय जीवन (लक्ष्य 14) को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आधे लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हो रही प्रगति या तो रुक गई है या फिर उसकी गति बहुत धीमी है। इसके बावजूद एशिया-पैसिफिक के कुछ क्षेत्रों में इन लक्ष्यों

को हासिल करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए पूर्वी और उत्तर पूर्वी एशिया में गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति हुई है। इसके साथ ही साफ पानी और स्वच्छता की दिशा में भी प्रगति हुई है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में इनोवेशन और डिजिटों के लक्ष्य में सफलता मिली है। हालांकि यहां के यादातर क्षेत्र पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्षरत हैं।

कोरोना ने डाला है सबसे यादा बुरा असर- यह रिपोर्ट ऐसे समय में पेश की गई है जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से उपजे संकट से जूझ रहा है, ऐसे में उसका एशिया-पैसिफिक क्षेत्र पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक ही है। जो सतत विकास से जुड़े इन 17 लक्ष्यों पर भी स्पष्ट रूप से दिखता है। यदि मातृ-मृत्यु दर की बात करें तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 14 देशों में उसके बढ़ने की आशंका है। यह 2020 के आधार पर देखें तो इसके प्रति लाख जीवित जनों पर 184 का अनुमान था जो सबसे खराब स्थिति में बढ़कर 263 पर जा सकती है। इसी तरह छह महीनों में इस क्षेत्र में 5 वर्ष से कम उम्र के 5 लाख से यादा बच्चों की मृत्यु का अनुमान है। यहां के करीब आधे देश आर्थिक विकास की गति में नकारात्मक बृद्धि देख रहे हैं। इसी तरह इस महामारी के चलते जून से अगस्त 2020 के बीच बुजुर्ग लोगों की दी जाने वाली 70 फीसदी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं बाधित हो गई थी। आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र के करीब 64 करोड़ लोग महामारी से फैले ही अलग-अलग तरह से गरीबी की मार झेल रहे थे, जिनके इस महामारी में दोगुना हो जाने की सम्भावना है। अनुमान है कि इस महामारी के चलते करीब 63.6 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी की चपेट में होंगे। साथ ही 2020 के अंत तक 7.1 करोड़ बच्चे पैसे की तंगी का शिकार हो चुके हैं।



यदि शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र के 85 करोड़ छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ा है और सितंबर 2020 तक उन्होंने अपना आधा साल बर्बाद कर दिया था। इसी तरह यदि बेरोजगारी की बात करें तो 2019 की तुलना में 2020 में करीब 1.5 करोड़ अतिरिक्त लोग बेरोजगार होंगे, जिसके लिए यह महामारी ही जिम्मेवार है। यहां के मजदूर अपनी मजदूरी का करीब 7.1 फीसदी हिस्सा 2020 में गंवा चुके हैं, जोकि करीब 72,58,405 करोड़ रुपए के बराबर है। अप्रैल 2020 में हुए लॉकडाउन ने इस क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र से जुड़े करीब 82.9 करोड़ मजदूरों पर असर डाला था। इसी तरह पर्यावरण के मामले में इस क्षेत्र के 11 देशों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस क्षेत्र के टटीय इलाकों की सुरक्षा में निश्चित रूप से कुछ प्रगति हुई है लेकिन स्थायी मत्स्य पालन से होने वाले आर्थिक लाभ और महासागरों की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिली है। क्षेत्र में पानी को लेकर जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2000 के बाद से इसकी स्थिति काफी खराब हो गई है। जिस पर ध्यान देना जरूरी है।

(साभार)

स्वच्छ भारत मिशन से साल भर में हर परिवार को हुआ करीब 53,536 रुपए का फायदा

एक शोध से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) से साल भर में हर घर को करीब 53,536 रुपए (727 डॉलर) का फायदा हुआ। जनल वर्ल्ड डेवलपमेंट में द्व्ये इस अध्ययन के अनुसार यदि इस मिशन से हुए फायदे को देखें तो, 10 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर जितना खर्च किया गया है वो उससे 4.3 गुना ज्यादा है। शोध के अनुसार जहां इस मिशन के चलते गरीब तबके को इसकी लागत का करीब 2.6 गुना फायदा हुआ है, वही समाज को 5.7 गुना फायदा पहुंचा है। यदि इसकी लागत और लाभ के अनुपात को देखें तो दस सालों में घरेलू खर्च पर जो रिटर्न है वह लागत का 1.7 गुना है। जबकि समाज को इसकी लागत की तुलना में करीब 4.3 गुना ज्यादा पहुंचा फायदा है। अध्ययन के अनुसार साल भर में हर घर को जो करीब 53,536 रुपए का लाभ पहुंचा है, उसका 55 फीसदी दस्त की घटनाओं में कमी के कारण स्वास्थ्य को हुए लाभ के रूप में है। जबकि इससे समय की जो बचत हुई है वो इसके लाभ के 45 फीसदी के बराबर है। गैरितलब है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुवात अक्टूबर 2014 में की गई थी। यह मिशन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। जिसका उद्देश्य खुले में शौच की शहरी घरों में शौचालय नहीं थे। साथ ही 52.2 करोड़ लोग खुले में शौच कर रहे थे। वहीं इस मिशन के अंतर्गत करीब 10,69,67,234 शौचालय बनाए गए थे। आज 6 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच जैसी कृती में मुक्त हो चुके हैं। इस मिशन में हर शौचालय के लिए औसतन 29,162 रुपए (396 डॉलर) का भुगतान किया गया था, जोकि प्राप्त सम्बिद्धि से दोगुना है। जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 9,352.4 रुपए (127 डॉलर) और परिवार की हिस्सेदारी 19,736 रुपए (268 डॉलर) की थी। इस 19,736 रुपए में से 18,926 रुपए (257 डॉलर) नकद और 810 रुपए (11 डॉलर) समय के रूप में खर्च किये गए थे। अध्ययन के अनुसार दो-तिहाई (69.5 फीसदी) से अधिक परिवारों को औसतन 13,476 रुपए (183 डॉलर) की सरकारी सम्बिद्धि मिली थी। जबकि इन परिवारों में से 63.8 फीसदी ने सरकारी सम्बिद्धि के ऊपर हर टायलेट पर औसतन 11,341 रुपए (154 डॉलर) का खर्च अपनी जेब से किया था। इस शोध के लिए किए गए सर्वे में 12 राज्यों के 10,051 ग्रामीण परिवार को शामिल किया गया था। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और असम शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में खुले में शौच करने वालों में से 90 फीसदी लोग इन्हीं राज्यों से थे।